NAME OF THE NEWSPAPER जनसत्ता DATE: 18 SEP 2012

उम्मीदों के प्रतिनिधि

यह बहुत अफसोसनाक है कि आज हमारी संसदीय राजनीति उस अवस्था में पहुंच गई है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। कोई योजना और कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें घपले-घोटाले न हो रहे हों। इसलिए हमारे राजनेताओं की राज-काज चलाने की क्षमता पर ही सवाल उठने लगे हैं। सांसदों और विधायकों के चरित्र और चाल में भारी बदलाव आया है। इसकी झलक संसद और विधानसभाओं में भी देखी जा सकती है। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, घूंसे दिखाना, कागज छीनना-फाड़ना और कागज के प्रक्षेपास्त्र बना कर मंत्रियों पर फेंकना, कई बार हिंसा पर उतर आना, नारेबाजी, शोरगुल, हंगामा, अनुशासनहीनता, पीठासीन अधिकारी की अवज्ञा, अध्यक्ष के आसन के पास आकर धरना, और कार्यवाही को न चलने देना आदि से जन-प्रतिनिधियों के बारे में जनता की धारणा बदली है। अब वह पहले से अधिक सजग और चौकन्नी हो गई है। यह शुभ लक्षण है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कुछ राजनेता और सांसद इसे संसद की सर्वोच्चता पर हमला बता कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

हमारे सांसद आज इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि साठ वर्षों तक संसदीय लोकतंत्र यहां सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होने पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है, क्योंकि उनमें से अधिकतर डाले मतों के भी अल्पमत से जीत कर आते हैं और उनके विरुद्ध पड़े मतों की संख्या उनके पक्ष में पड़े मतों से अधिक होती है। इन तमाम खामियों को हमें दूर करना होगा, ताकि हमारी संसद वास्तव में जनता के बहुमत का प्रतिबिंब बन सके। यह अच्छी बात है कि राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के बावजूद संसद में अब भी अच्छे लोगों की संख्या बहुतायत में है। संसद सदस्यों के साथ-साथ अब राज्यसभा की सीटों तक क्रय-विक्रय एक बड़ी चुनौती है। इसकी वजह धनबल और

edit.jansatta@expressindia.com

बाहुबल को महत्त्व मिलना है। ऐसे लोगों के कारण ही संसद की गरिमा और उसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है। आज बिना बहस के बजट और कई विधेयकों को पारित कर दिया जाता है जिस पर चिंता भी जताई जाती है। संसद का कामकाज अब सदन के बजाय समितियों या मिनी हाउस द्वारा होने लगा है। इससे संसद और लोकतंत्र की गरिमा कम हुई है। अब अगर हमें संसद और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले ऐसा कुछ करना होगा जिससे संसद और सांसदों की प्रारंभिक गरिमा पुनर्स्थापित हो और फिर से उन्हें जनमत में आदर और स्नेह का स्थान मिल सके।

संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का ठीक होना आवश्यक है, लेकिन इन दलों के नेता अपने में सुधार लाने के बजाय यह कह कर जनता में भ्रम फैला रहे हैं कि संसद की सर्वोच्चता पर हमला किया जा रहा है और इस प्रयास को हम सहन नहीं करेंगे। जबकि संसद की सर्वोच्चता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार पर टिकी चुनाव प्रणाली को कैसे सुधारा जाए और देश में चौतरफा फैले भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाई जाए, ताकि जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अगर संसद अपनी सर्वोच्चता, गरिमा बनाए रखने, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ाने के प्रति वास्तव में संकल्पबद्ध है तो उसे संसद की कार्यवाही के साथ ही राजनीतिक और निर्वाचन प्रणाली के तौर-तरीकों में सुधार करना ही होगा ऐसा किए बगैर संसद का प्रभुत्व स्थापित होने वाला नहीं है।

राजनेताओं को इससे आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए कि संसद सर्वोच्च है और भारत दुनिया में लोकतंत्र की सफलता का सूचक है, क्योंकि अब यह महसूस किया जा रहा है कि लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप अनेक खामियों से ग्रस्त है। यह वही खामियां हैं जो जनता की बेचैनी बढ़ा रही हैं।

● *विमल श्रीवास्तव, दिल्ली विश्वविद्यालय*